456 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स (1964)

श्री वेंकट सीतारमंजनेय चावल और तेल मिल्स और अन्य -

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य आदि

(पीबी गजेंद्रगडकर, सीजे; केएन वांचू, जे; जेसी शाह,

एन. राजगोपाला अयंगर एवँ एस.एम. सीकरी, जे जे.)

मद्रास एसेंशियल आर्कटिकल्स कंट्रोल एंड रिक्विज़िशनिंग (अस्थायी) शक्तियाँ अधिनियम, 1949 (1949 का अनुच्छेद 29), एस.एस. 3(1)(2)द्वारा आपूर्ति की गई बिजली पर अधिनियम की प्रयोज्यता राज्य-विधानमंडल की मंशा, विचार-अधिसूचित राज्य द्वारा सहमत दर बढ़ाने के आदेश-क्या धारा के तहत वैध हैं। 3-विनियमित करना, का अर्थ-टैरिफ की वृद्धि-यदि उचित हो और आम जनता के हित में-चाहे अनुच्छेद का उल्लंघन हो। 14 और 19(1)-भारत का संविधान, अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) और (एफ).

पिछले कई वर्षों से प्रतिवादी राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गई थी और आपूर्ति के लिए नियम और शर्तों को निर्धारित करते हुए उनके बीच कई व्यक्तिगत समझौते पारित किए गए थे। इनमें से एक शर्त ने उस दर को निर्धारित किया जिस पर आपूर्ति पर शुल्क लगाया जाना था। इन समझौतों में राज्य को उनके संचालन के दौरान दरें बढ़ाने

के लिए अधिकृत करने वाला कोई प्रावधान नहीं था। प्रतिवादी राज्य ने सहमत दरों को बढ़ाने के लिए दो अधिसूचित आदेश जारी किए। आदेशों ने संकेत दिया कि वृद्धि को प्रेरित करने वाला मुख्य कारण यह था कि मौजूदा बिजली दरें जो कई साल पहले तैयार की गई थीं, पूरी तरह से अलाभकारी हो गई थीं और इसका मतलब था कि राज्य को लगातार घाटा हो रहा था। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दो आदेशों की वैधता को चुनौती दी। रिट याचिकाएँ स्वीकार कर ली गईं और प्रतिवादी को संशोधित दरें लागू करने से रोक दिया गया। इन निर्णयों को प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी, जिसने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस न्यायालय में अपील पर अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी के पास एस का सहारा लेकर अनुबंध की इस महत्वपूर्ण शर्त को बदलने वाली दर को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था। मद्रास आवश्यक वस्तु नियंत्रण और मांग; अस्थायीद्ध शक्तियां अधिनियम की धारा 3(1) कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करने की शक्ति को नागरिकों और नागरिकों के बीच लेनदेन के संबंध में लागू किया जाना था और इसे एक आवश्यक वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता था जो राज्य ने स्वयं आपूर्ति की कि विनियमित करने की शक्ति एस द्वारा प्रतिवादी को प्रदान की गई है। 3(1) में टैरिफ दर बढ़ाने की शक्ति शामिल नहीं हो सकती,

अधिसूचित आदेश अमान्य थे क्योंकि वे अनुच्छेद 19(1)(एफ) एवं (जी) के प्रावधानों और संविधान के 14 के अनुच्छेद का उल्लंघन करते थे.

अवधारित:

(1) अधिसूचित आदेशों की वैधता को इस आधार पर चुनौती कि वे अधिनियम की धारा 3(1) के दायरे से बाहर थे, कायम नहीं रह सकी।

राज्य किसी क़ानून से बंधा नहीं है जब तक कि इसे स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। इस नियम को लागू करने में अदालत को क़ानून के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर एक साथ विचार करके विधानमंडल की मंशा का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और अपना ध्यान किसी विशेष प्रावधान पर केंद्रित नहीं करना चाहिए जो विवाद में हो सकता है।

जहां सवाल यह नहीं है कि क्या राज्य क़ानून से बंधा है, लेकिन क्या वह क़ानून के प्रावधान के लाभ का दावा कर सकता है ऐसी स्थिति में एक ही रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन लागू करना पड़ सकता है.

जहां क़ानून जनता की भलाई के लिए हो सकता है और इसके प्रावधानों द्वारा दिए गए लाभ का दावा करके राज्य यह आरोप लगा सकता है कि वह जनता की भलाई कर रहा है. तब भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने के लिए विधायिका का इरादा क्या था.

निदेशक राशनिंग और वितरण बनाम कलकत्ता निगम, (1961) 1 एस.सी.आर. 158 और बंबई प्रांत बनाम बंबई शहर का नगर निगम, (1945-46) एल.आर. 73 आई.ए. 271, आवेदन किया गया।

(2) अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में सामान्य रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन के नियम को अपनाया जाना चाहिए, धारा 3 को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसकी उचित व्यवस्था में विचार किया जाना चाहिए और अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इसके जीन के लिए उचित सम्मान होना चाहिए.

(3) अधिनियम का उद्देश्य उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुरक्षित करना है, यह अप्रासंगिक होगा कि आपूर्ति कौन करता है, उचित मूल्य पर आपूर्ति को विनियमित करना प्रासंगिक है।

(4) यह सर्वविदित है कि धारा 3 का उपवाक्य (2) का कार्य केवल उदाहरणात्मक है। दूसरे शब्दों में धारा 3 का उपवाक्य (1)(2) की व्याख्या करने के लिए उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यह मान लेना है कि जो कुछ भी उपवाक्य में शामिल है।

किंग एम्परर बनाम सिबनाथ बनर्जी, 72 आई.ए. 241 और संतोष कुमार जैन बनाम राज्य, (1951) एस.सी.आर. 303, लागू.

(5) रेगुलेट शब्द इतना व्यापक है कि यह राज्य को दर बढ़ाकर या घटाकर दर को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, परीक्षण यह है

कि इसे बनाए रखने, बढ़ाने या बढ़ाने के लिए क्या करना आवश्यक या समीचीन है। संबंधित आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति और उसके न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्य पर उसकी उपलब्धता की व्यवस्था करना।

(6) इस मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ में किए गए परिवर्तन उचित थे और आम जनता के हित में थे।

(7) अपील के रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कोई दलील को भी उठाया जा सकता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपील संख्या 429, 439, 591, 592, 597, 689, 694, 724, 725 और 727/1962 और 15, 139, 140, 159, 267 से 269, 331, 334, 337, 340, 342, 343, 347, 352, 389, 746 और 748/1963.

19 दिसंबर, 1958, 7 मार्च, 1959, 11 मार्च, 1959 के निर्णयों और आदेश के विरुद्ध अपील। 22 अप्रैल,1959, 24 अप्रैल, 1959 रिट में अपील संख्या 135, 1957 की 122 आदि।

टी. वी. आर. टाटाचारी, अपीलकर्ताओं के लिए (सी.ए. संख्या 429 से 434 और 1962 के 694 और सी.ए. संख्या 269/63 में)। एम. सी. सीतलवाड, पी. कोडंडारामय्या, ई. वी. भागरथी

अपीलकर्ताओं के लिए राव और टी. वी. आर. टाटाचारी (सी.ए. संख्या में) 438 और 439/62)। अपीलकर्ताओं के लिए एम. सी. सीतलवाड, और आर. गणपति अय्यर, (सी. ए. संख्या 436, 437, 724, 725 और 727/62 में)।

अपीलकर्ताओं के लिए के. श्रीनिवासमूर्ति और नौनित लाल, (सी. अस. संख्या 591, 582, 597, और 689/62 और 140, 267 और 268/63 में)।

अपीलकर्ताओं के लिए के. श्रीनिवासमूर्ति और नौनित लाल, (सी.ए. संख्या 591, 582, 597, और 689/62 और 140, 267 और 268/63 में)।

अपीलकर्ताओं के लिए के.जयराम और आर.त्यागराजन, सी, संख्या 139, 159, 330, 334, 337, 340, 342, 343, 347 और 352/63). अपीलकर्ताओं के लिए के.आर.चौधरी (सी.ए. संख्या 15 और 63 में से 389 में)

अपीलकर्ता के लिए ए. वेदवल्ली और ए. वी. रंगम (सी. अस. संख्या 746, और 63 में से 748)

उत्तरदाताओं के लिए डी. नरसराजू, टी. अनंत बाबू, एम. वी. गोस्वामी और बी. आर. जी. के. अचार (सी. अस. संख्या 435- में) 437, 724, 725 और 727/62)।

उत्तरदाताओं के लिए डी. नरसाराजू, टी. अनंत बाबू, योगेश्वर प्रसाद और बी.आर.जी.के. अचार (सी. अस. संख्या 429- 434, 438, 439 और 694/62 और 63 में से 269)

उत्तरदाताओं के लिए डी. नरसराजू, टी. अनंत बाबू, एम.एस. /62). प्रतिवादी की ओर से जे. वी. के. सरमा और टी. सत्यनारायण क्रमांक 2 (सी.ए. क्रमांक 592/62 में)।

उत्तरदाताओं के लिए डी. नरसराजू, टी. अनंत बाबू, आर. गोपालकृष्णन और बी.आर.जी.के. अचार और 746-748/63).

25 मार्च, 1964 को न्यायालय का निर्णय गजेंद्रगडकर, सीजे द्वारा पारित किया गया.

गजेंद्रगडकर, सीजे- कानून का मुख्य प्रश्न जो इन 37 सिविल अपीलों के इस समूह में उठता है, वह मद्रास एसेंशियल आर्टिकल्स कंट्रोल एंड रिक्विजिशनिंग (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1949 (1949 की संख्या 29) (इसके बाद इसे कहा जाएगा) की धारा 3 के निर्माण से संबंधित है। 'अधिनियम')। जिस विवाद ने इन अपीलों को जन्म दिया है, वह प्रतिवादी, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा क्रमशः 28 जनवरी, 1955 और 30 जनवरी, 1955 को जारी किए गए दो अधिसूचित आदेशों की वैधता पर केंद्रित है, और यह अपीलकर्ताओं का तर्क है कि कहा कि अधिसूचित आदेश एस के दायरे से बाहर हैं। 3. इन सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं को पिछले कई वर्षों से

प्रतिवादी द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है, और 1946 से 1952 की अवधि के दौरान उनके और प्रतिवादी के बीच कई व्यक्तिगत समझौते पारित किए गए हैं, जिसमें नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन पर उक्त आपूर्ति की जाएगी। उन्हें। इनमें से एक शर्त में वह दर निर्धारित की गई जिस पर उपभोक्ताओं से बिजली की आपूर्ति का शुल्क लिया जाना था। आक्षेपित आदेशों में इस दर को बढ़ाने का दावा किया गया है, और अपीलकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिवादी के पास एस का सहारा लेकर अनुबंध की इस महत्वपूर्ण शर्त को अपने पूर्वाग्रह के तहत बदलने का कोई अधिकार नहीं था। 3(1) और उस संबंध में अधिसूचित आदेश जारी करना। वस्तुतः यह हमारे सामने मौजूद पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति है।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि मद्रास सरकार, और उसके बाद, उसके उत्तराधिकारी, प्रतिवादी के पास पूरे राज्य के लिए एक ही पावर ग्रिड सिस्टम था जिसमें तुंगभद्रा और मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम और नेल्लोर का थर्मल सिस्टम शामिल था। संपूर्ण ऊर्जा को एक विद्युत प्रणाली में एकीकृत किया गया था। मद्रास सरकार ने वर्ष 1951 और 1952 के लिए निर्दिष्ट दरों, जिन्हें टैरिफ कहा जाता था, पर थोक में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अपीलकर्ताओं सहित राज्य के कई उपभोक्ताओं के साथ समझौते किए। ये समझौते दस वर्षों तक लागू रहने थे। साल। यह सामान्य बात है कि इन समझौतों में सरकार को उनके संचालन के दौरान दरें बढ़ाने के लिए अधिकृत करने वाला कोई प्रावधान नहीं था। तय किए गए शुल्कों की

गणना उपभोग इकाइयों के बढ़ते स्लैब के अनुसार वर्गीकृत प्रतिगामी दरों पर की गई थी, और मांग शुल्क सहित कुल इकाई दरें मासिक न्यूनतम भुगतान और गारंटीकृत खपत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 66 आने से अधिक नहीं होनी थीं। आंध्र सरकार ने तब सहमत दरों को बढ़ाते हुए क्रमशः मचकुंड और नेल्लोर, और तुंगभद्रा और चित्तूर जिला क्षेत्रों से संबंधित दो विवादित आदेश जारी किए। ये बढ़ी हुई दरें उक्त आदेशों से जुड़ी अनुसूची ए और बी में निर्दिष्ट थीं। इन आदेशों के अनुसार, ये बढ़े हुए टैरिफ उस तारीख से प्रभावी होने थे जिस दिन फरवरी, 1955 के महीने में मौसम रीडिंग ली जानी थी और भविष्य के लिए लागू होनी थी। इस प्रकार इन आदेशों से प्रभावित दरों में वृद्धि पूर्वव्यापी रूप से नहीं, बल्कि भावी रूप से लागू होगी। आक्षेपित आदेशों से संकेत मिलता है कि उक्त आदेशों को प्रेरित करने वाला मुख्य कारण यह ज्ञान था कि मौजूदा बिजली दरें, जो लगभग 15 साल पहले तैयार की गई थीं, पूरी तरह से अलाभकारी हो गई थीं; श्रम की लागत और सभी सामग्रियों के मूल्य स्तर में भारी वृद्धि हुई थी; और इसका मतलब अनिवार्य रूप से सरकार को लगातार बढ़ता घाटा था। महालेखाकार ने इस आवर्ती हानि के संबंध में प्रश्न पूछे और राज्य सरकार का ध्यान बिजली प्रणाली के कामकाज में घाटे की ओर आकर्षित किया। तदनुसार, मद्रास राज्य में टैरिफ में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया गया था, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन तब विचाराधीन था। प्रतिवादी राज्य के अस्तित्व में आने के बाद,

इसके मुख्य अभियंता ने संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में टैरिफ में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा विवादित अधिसूचित आदेश जारी किये गये।

3. अपीलकर्ता स्वाभाविक रूप से इन आदेशों से व्यथित थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिवादी द्वारा उन्हें बिजली की आपूर्ति के लिए दरों का भुगतान करने का दायित्व बढ़ा दिया था। तदनुसार, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने कला के तहत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया। संविधान के 226, और दो विवादित आदेशों की वैधता को चुनौती दी। इन रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं की याचिका को बरकरार रखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी को दिए गए अधिकार द्वारा विवादित आदेश उचित नहीं थे। अधिनियम के 3, और अनधिकृत, अवैध और निष्क्रिय थे। परिणामस्वरूप, हमारे समक्ष कुछ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका को अनुमति दी गई और संशोधित टैरिफ दरों को लागू करने से रोकते हुए प्रतिवादी के खिलाफ एक उचित आदेश जारी किया गया।

इन निर्णयों को प्रतिवादी द्वारा कई पत्र पेटेंट अपीलें दायर करके चुनौती दी गई थी। जिस डिवीजन बेंच ने इन लेटर्स पेटेंट अपीलों पर सुनवाई की, उसने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया; यह माना गया कि इसके निष्पक्ष और उचित निर्माण पर, एस। 3 ने प्रतिवादी को विवादित आदेश

जारी करने का अधिकार प्रदान किया, और इसलिए, उक्त आदेशों की वैधता को दी गई चुनौती कायम नहीं रह सकी। इसीलिए प्रतिवादी द्वारा पसंद की गई लेटर्स पेटेंट अपीलों को अनुमति दी गई और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलकर्ता उक्त उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ इस न्यायालय में आये हैं।

5. डिवीजन बेंच द्वारा इस बिंदु पर अपना निर्णय सुनाए जाने के बाद, अन्य उपभोक्ताओं द्वारा कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गईं, और स्वाभाविक रूप से उन्हें सुनने वाले एकल न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच के फैसले का पालन किया और उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। जो उपभोक्ता विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित थे, उन्हें विशेष अनुमति के माध्यम से सीधे इस न्यायालय में आने की अनुमति दी गई, क्योंकि जो मुद्दे वे उठाना चाहते थे वे बिल्कुल वही थे जो यहां आए अन्य उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए थे। डिवीजन बेंच के मुख्य फैसले के खिलाफ कोर्ट. इस प्रकार अपीलों के वर्तमान समूह में वे मामले शामिल हैं जिनका निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा किया गया है, साथ ही वे मामले जिनका निर्णय एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया है, और वे सभी निर्माण के बारे में एक ही सामान्य प्रश्न उठाते हैं। एस। अधिनियम के 3, और विवादित अधिसूचित आदेशों की वैधता।

6. एस की व्याख्या करने के प्रश्न पर स्वयं को संबोधित करने से पहले। 3, अधिनियम के विधायी इतिहास को दोबारा दोहराना आवश्यक है। यह याद किया जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत सरकार ने 29 सितंबर, 1939 को भारत रक्षा अधिनियम (संख्या 35, 1939) पारित किया था। उक्त अधिनियम के 2 में, केंद्र सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए जिन्हें भारत की रक्षा नियम के रूप में जाना जाता है। इन नियमों में नियम 81(2) था जो केंद्र सरकार को ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता था जो केंद्र सरकार को "ब्रिटिश भारत की रक्षा, या युद्ध के कुशल अभियोजन, या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना"। ये नियम युद्ध की निरंतरता के दौरान लागू थे। युद्ध समाप्त होने के बाद, यह महसूस किया गया कि देश में आर्थिक स्थिति गंभीर बनी हुई है, और आर्थिक मामलों के उचित विनियमन के लिए, भारत की रक्षा नियम 81(2) के तहत जारी आदेशों को जारी रखना आवश्यक समझा गया।), क्योंकि तब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी बहुत अधिक देखने को मिलती थी। आदेशों को जारी रखने का उद्देश्य समुदाय को उचित मूल्य पर बड़े पैमाने पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उनके समान वितरण को सुरक्षित करना था। समय के साथ, भारत रक्षा अधिनियम 1946 में समाप्त हो गया, लेकिन केंद्रीय विधानमंडल ने इसकी जगह लेने के लिए एक और अधिनियम पारित करना आवश्यक समझा और वह था आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां)

अधिनियम, 1946 (1946 का क्रमांक 24)). इसी तर्ज पर, मद्रास विधानमंडल ने 1946 में एक अधिनियम पारित किया (1946 का क्रमांक 14)। बाद में, इसे 1949 के अधिनियम संख्या 29 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिससे हम वर्तमान अपीलों में चिंतित हैं। राज्यों के पुनर्गठन की योजना के तहत प्रतिवादी राज्य के गठन के बाद, इसने 1955 का अधिनियम संख्या 1 पारित किया और इस अधिनियम को 21 जनवरी, 1955 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम द्वारा, प्रतिवादी राज्य का विधानमंडल वस्तुतः मद्रास अधिनियम को अपनाया। परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश, सारतः, धारा के संदर्भ में हैं। मद्रास अधिनियम के 3

7. इससे पहले कि हम इस विषय से अलग हों, यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब मद्रास अधिनियम पारित किया गया था, तो इसकी अनुसूची में एस द्वारा परिभाषित आवश्यक लेखों की एक सूची दी गई थी। 2(ए) और ये अनुच्छेद संख्या में 12 थे। जब आंध्र विधानमंडल ने 1955 का अधिनियम संख्या 1 पारित किया और अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुच्छेदों की अनुसूची को अपनाया, तो इन अनुच्छेदों की संख्या घटाकर दो कर दी गई; वे चारकोल और विद्युत ऊर्जा हैं। आंध्र अधिनियम मूल रूप से 25 जनवरी, 1956 तक लागू रहने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे समय-समय पर जारी रखा गया। यह सामान्य आधार है कि जब विवादित आदेश पारित किए गए थे, तब अधिनियम की धारा 3 लागू थी और

वर्तमान अपीलों पर इस आधार पर तर्क दिया गया है कि उक्त धारा संवैधानिक रूप से वैध है, इसलिए मुख्य बिंदु जो हमारे निर्णय की मांग करता है वह है उक्त अनुभाग का निर्माण.

8. अपीलकर्ताओं के लिए श्री सीतलवाड का तर्क है कि व्याख्या में। 3, हमें एस में प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। 3 अलगाव में, लेकिन अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ उक्त धारा को अवश्य देखें। उनका आग्रह है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के लिए आवश्यक है कि हमें अधिनियम के सभी प्रावधानों को इस प्रकार बनाना चाहिए कि उनके बीच किसी भी संघर्ष या प्रतिकूलता से बचा जा सके। इस प्रकार, उनके अनुसार, धारा 3, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रतिवादी को प्रतिवादी द्वारा उन्हें की गई ऊर्जा की आपूर्ति के संबंध में अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रभार्य टैरिफ दर को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की पूरी योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को विनियमित करने की शक्ति जो राज्य सरकार को प्रदान की गई है, उसे नागरिकों और नागरिकों के बीच लेनदेन के संबंध में लागू किया जाना है और राज्य को किसी आवश्यक वस्तु पर लागू नहीं किया जा सकता है। स्वयं आपूर्ति करता है। उनका सुझाव है कि यह अजीब होगा, अगर राज्य सरकार को उन दरों को विनियमित करने के लिए एक अधिसूचित आदेश जारी करने की शक्ति दी जाए, जिस पर उसे ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए, जिसका वह खुद उत्पादन करती है।

इसलिए, उपभोक्ताओं को ऊर्जा आपूर्ति के मामले में राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यवहार धारा के प्रावधानों से बाहर माना जाना चाहिए। 3, और इससे विवादित आदेश अमान्य हो जायेंगे।

9. यह प्रश्न कि क्या राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधायी अधिनियमों के प्रावधानों से बाध्य होगी, कभी-कभी न्यायिक राय में मतभेद पैदा हो जाता है; लेकिन इस न्यायालय के निर्णय में राशन एवं वितरण निदेशक बनाम. कलकत्ता निगम और अन्य,यह मान लिया जाना चाहिए कि इस प्रश्न का समाधान हो गया है। उस मामले में दिए गए बहुमत के निर्णय का प्रभाव बंबई प्रांत बनाम बंबई शहर के नगर निगम 73 आईए 271 में प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रतिपादित क़ानूनों की व्याख्या के नियम की वैधता को मान्यता देना है और वह नियम यह है कि राज्य यह किसी कद से बंधा हुआ नहीं है जब तक कि यह स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान न किया गया हो। इस नियम को लागू करने में, यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि न्यायालय को कद के सभी प्रासंगिक प्रावधानों पर एक साथ विचार करके विधानमंडल की मंशा का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए और अपना ध्यान किसी विशेष प्रावधान पर केंद्रित नहीं करना चाहिए जो पार्टियों के बीच विवाद में हो सकता है। यदि, क़ानून के सभी प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के बाद, न्यायालय संतुष्ट है कि आवश्यक निहितार्थ से क़ानून द्वारा लगाए गए दायित्व को राज्य के खिलाफ लागू किया जाना चाहिए, तो उस निष्कर्ष को

अपनाया जाना चाहिए। यदि इस आशय की स्पष्ट शर्तें हैं, तो निःसंदेह, कोई कठिनाई नहीं है। इस जटिल प्रश्न से निपटने में, कभी-कभी यह जांच करना भी आवश्यक होता है कि क्या यह निष्कर्ष कि राज्य किसी दिए गए क़ानून के विशिष्ट प्रावधान से बंधा नहीं है, क़ानून के कामकाज में बाधा उत्पन्न करेगा, या क़ानून की असंगत स्थिति को जन्म देगा। अपनी प्रभावकारिता खो सकता है, और यदि इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर यह इंगित करता है कि क़ानून द्वारा लगाए गए दायित्व को राज्य के विरुद्ध लागू किया जाना चाहिए, तो न्यायालय आवश्यक निहितार्थ से यह निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक होगा कि राज्य, वास्तव में, बाध्य है क़ानून.

10. हालाँकि, जहाँ सवाल इतना नहीं है कि क्या राज्य क़ानून से बंधा है, बल्कि यह है कि क्या वह किसी क़ानून के प्रावधान के लाभ का दावा कर सकता है, निर्माण का वही नियम लागू करना पड़ सकता है। जहां क़ानून जनता की भलाई के लिए हो सकता है, और इसके प्रावधानों द्वारा दिए गए लाभ का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति यह आरोप लगा सकता है कि वह जनता की भलाई कर रहा है, तब भी यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि क्या विधायिका का इरादा ऐसा करने का था राज्य पर लागू प्रासंगिक प्रावधान। यह स्थिति बंबई प्रांत 73 आईए 271 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय द्वारा भी स्थापित की गई है और यह अभी भी इस देश में एक कानून के रूप में जारी है।

11. संयोग से, हम यह जोड़ सकते हैं कि जहां क्राउन किसी क़ानून का लाभ उठाना चाहता है और आग्रह करता है कि यद्यपि वह क़ानून से बाध्य नहीं है, लेकिन वह इसका लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है, अंग्रेजी कानून आसानी से ऐसी याचिका पर विचार नहीं करता है, हालाँकि कुछ न्यायिक घोषणाओं में इसके विपरीत टिप्पणियाँ की गई हैं। जैसा कि हैल्सबरी बताते हैं,

> "यह कहा गया है कि, जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, क्राउन एक कद का लाभ उठा सकता है, भले ही वह इससे बाध्य न हो।" यह बयान देने के बाद, हेल्सबरी ने यह कहते हुए सावधानी का एक नोट जोड़ा है कि "इस नियम के लिए केवल पतला अधिकार है, और चूंकि नियम और ऐसे प्राधिकरण दोनों पर भी संदेह किया गया है, इसलिए नियम को शायद नहीं माना जा सकता है स्थापित कानून [इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानून, खंड 36, पृष्ठ 432, पैरा 654]"।

12. इसी आशय की टिप्पणी मैक्सवेल द्वारा की गई है जब उन्होंने सर जॉन साइमन द्वारा व्यक्त किए गए विचार को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया कि जो निर्णय वैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए क्राउन के अधिकार को मान्यता देते हैं

"एक असफल तर्क में एक अंश के साथ शुरू होते हैं एक कानून अधिकारी का जो अदालत के समक्ष मामले के लिए भी प्रासंगिक नहीं था, लेकिन जिसे एक पाठ-लेखक द्वारा हटा दिया गया है और सदियों से दोहराया गया है जब तक कि यह नहीं माना जाता कि इसका कुछ आधार होना चाहिए [संविधि की व्याख्या पर मैक्सवेल, 11वां संस्करण पी. 136]"।

13. इसलिए, एस का अर्थ निकालने में। अधिनियम के 3 में, हम प्रतिवादी को कृत्रिम नियम पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि प्रतिवादी धारा के तहत लाभ का दावा करता है। 3, उस निर्माण को अपनाया जाना चाहिए जो इस तरह के दावे का समर्थन करता है। इस प्रकार, स्थिति यह है कि जब हम एस का अर्थ निकालते हैं। 3, हमें निर्माण के सामान्य नियम को अपनाना चाहिए; हमें एस नहीं पढ़ना चाहिए. 3 अलगाव में, लेकिन इसकी उचित सेटिंग में इस पर विचार करना चाहिए और अधिनियम के अन्य प्रावधानों, और इसकी सामान्य योजना और उद्देश्य के लिए उचित सम्मान होना चाहिए।

14. श्री सीतलवाड के मुख्य तर्क पर लौटते हुए, यह माना जा सकता है कि जब 1949 में अधिनियम पारित किया गया था, तो मुख्य रूप से और मुख्य रूप से एस द्वारा प्रदत्त शक्ति। 3 राज्य सरकार का उद्देश्य एक

नागरिक द्वारा दूसरे नागरिक को की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को विनियमित करना रहा होगा। राज्य ने तब बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रवेश नहीं किया था और जब एस. 3(1) आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए अधिसूचित आदेशों पर विचार करते हुए, विधायिका के मन में राज्य द्वारा स्वयं की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो सकती है। यह श्री सीतलवाड के निर्माण के पक्ष में एक बिंदु है। यदि हम अधिनियम की योजना की जांच करते हैं, तो यह भी मानना होगा कि कुछ प्रावधान राज्य पर लागू नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एस का प्रावधान लें। 4 जो संपत्तियों की मांग और अधिग्रहण की शक्तियों से संबंधित है, और बाद के दो खंड जो क्रमशः मुआवजे के भुगतान और मांग से मुक्ति से संबंधित हैं; ये प्रावधान राज्य पर लागू नहीं हो सकते हैं। फिर से, कृषि पर नियंत्रण लें, जिस पर एस द्वारा विचार किया गया है। 7; यह राज्य पर लागू नहीं होगा. धारा 12 जो दंड से संबंधित है, राज्य पर भी लागू नहीं हो सकती है, और इसलिए, एस। 13 लागू नहीं होगा, क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उकसाने और सहायता से संबंधित है। इसलिए, अधिनियम की सामान्य योजना और इसके कुछ प्रावधान यह सुझाव देते प्रतीत होते हैं कि राज्य इस अधिनियम पर विचार नहीं कर रहा होगा।

15. लेकिन यह स्पष्ट है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम जिस पर श्री सीतलवाड ने पूरी तरह से अपना मामला टिकाया है, उनके द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है यदि एस में इस्तेमाल किए गए शब्द। 3 वह निर्माण करने में सक्षम हैं जो वह सुझाते हैं। यदि उक्त शब्द दो निर्माणों में सक्षम हैं जिनमें से एक अपीलकर्ताओं के मामले का समर्थन करता है और दूसरा प्रतिवादी के मामले का, तो पहले निर्माण को अपनाना वैध होगा, क्योंकि इसमें एस के प्रावधानों को सुसंगत बनाने का गुण है। 3 अधिनियम की सामान्य योजना और उद्देश्य के साथ। दूसरी ओर, यदि एस में प्रयुक्त शब्द। 3(1) उस निर्माण के लिए उचित रूप से सक्षम नहीं हैं जिसके लिए अपीलकर्ता तर्क देते हैं, तो न्यायालय के लिए उन शब्दों के दायरे को मनमाने ढंग से केवल कल्पित वस्तु और योजना के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से सीमित करना अनुचित और नाजायज होगा। अधिनियम। इसलिए एस में प्रयुक्त शब्दों की जांच जरूरी है. 3 बहुत सावधानी से. आइये सबसे पहले पढ़ते हैं एस. 3(1) :-

> "राज्य सरकार जहां तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने, बढ़ाने या सुनिश्चित करने या उचित कीमतों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक या समीचीन लगती है, अधिसूचित आदेश द्वारा, विनियमन या निषेध के लिए प्रावधान कर सकती है।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और परिवहन और उसमें व्यापार और वाणिज्य"।

16. उपधारा (2) में प्रावधान है कि उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके तहत बनाया गया आदेश खंड (ए) से (के) में निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए प्रदान कर सकता है। इनमें से अधिकांश वस्तुएँ राज्य पर लागू नहीं हो सकती हैं, जबकि, अनुमानतः, कुछ वस्तुएँ उस पर लागू हो सकती हैं।

17. धारा 3(1) का उद्देश्य स्पष्ट रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उचित मूल्य पर उनके समान वितरण और उपलब्धता की व्यवस्था करना है। यदि विद्युत ऊर्जा अनुसूची में उल्लिखित आवश्यक वस्तुओं में से एक है, तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि धारा के तहत एक अधिसूचित आदेश जारी किया जा सकता है। 3(1) उक्त ऊर्जा की आपूर्ति को विनियमित करने और इसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए। वास्तव में, यह विवादित नहीं है और इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि यदि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किसी निजी लाइसेंसधारी द्वारा किया जाता है और फिर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी आपूर्ति एस की शरारत के अंतर्गत आएगी। 3(1), और जिन शर्तों पर इसे उपभोक्ताओं के लिए लागू किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उन्हें एक अधिसूचित आदेश द्वारा विनियमित किया जा

सकता है। इस बात पर भी कोई गंभीर विवाद नहीं हो सकता है कि विद्युत ऊर्जा के एक निजी आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता के बीच हुए अनुबंध की शर्तों को एक अधिसूचित आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकता है। धारा 3(i) निस्संदेह राज्य सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या वितरण के संबंध में अनुबंध की शर्तों को बदलने और संशोधित करने की शक्ति प्रदान करती है। यदि ऐसा है, तो एस के एक सादे पढ़ने पर। 3(1) इस तर्क को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति जो एस में शामिल है। 3(1) यदि यह किसी निजी निर्माता द्वारा बनाया गया है तो राज्य सरकार द्वारा उत्पादित होते ही उक्त धारा से बाहर हो जाना चाहिए। जोर इस बात पर नहीं है कि कौन उत्पादन और आपूर्ति करता है, बल्कि जोर इस बात पर है कि आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर समान वितरण और आपूर्ति जारी रहे। यदि वस्तु जो एस. 3(1) में आवश्यक वस्तुओं का ऐसा न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है, तो वह वस्तु अभी भी एस के प्रावधानों को आकर्षित करना जारी रखेगी। 3(1) भले ही आवश्यक वस्तु का उत्पादन राज्य द्वारा किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा सकती है। एस में प्रयुक्त शब्द. 3(1) इतने स्पष्ट, असंदिग्ध और व्यापक हैं कि उनके दायरे को कृत्रिम रूप से इस आधार पर सीमित करना अनुचित होगा कि अनुभाग की व्यापक भाषा को प्रभावित करके, हम ऐसे परिणाम पर पहुंच सकते हैं जो पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण या सुसंगत नहीं है

अधिनियम का अनुमानित उद्देश्य और उद्देश्य। वास्तव में, जैसा कि हमने अभी संकेत दिया है, यदि अधिनियम का उद्देश्य उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, तो यह अप्रासंगिक होगा कि आपूर्ति कौन करता है; उचित मूल्य पर आपूर्ति को विनियमित करना प्रासंगिक है। इसलिए, हम श्री सीतलवाड के इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि एस. 3(1) प्रतिवादी को उसके और अपीलकर्ताओं के बीच समझौते की शर्तों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।

18. निस्संदेह, श्री सीतलवाड ने तर्क दिया कि एस की व्याख्या में। 3(1), हम इस तथ्य को ध्यान में रख सकते हैं कि एस के तहत अधिकांश खंड। 3(2) प्रतिवादी राज्य पर लागू नहीं होगा, और इसलिए, वह वस्तुतः सुझाव देता है कि भले ही एस में शब्द हों। 3(1) विस्तृत हो सकते हैं, उनकी चौड़ाई उपधारा (2) द्वारा निर्धारित खंडों के सीमित दायरे द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए। हम इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हैं. किंग एम्परर बनाम सिबनाथ बनर्जी 72 आईए 241 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि धारा के खंड (2) की तरह एक खंड का कार्य। 3 केवल उदाहरणात्मक (वीडियो भी देखें)। संतोष कुमार जैन बनाम. भारतीय राज्य संघ (हस्तक्षेपकर्ता),. दूसरे शब्दों में, एस के खंड (1) और (2) की व्याख्या करने के लिए उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। 3 यह मान लेना है कि जो कुछ खंड (2) में शामिल है वह खंड (1) में भी शामिल है। इसका मतलब यह नहीं है कि

यदि खंड (1) के शब्द खंड (2) में शामिल नहीं किए गए मामलों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं, तो इस कारण से, उन्हें एक संकीर्ण निर्माण प्राप्त करना होगा। इसलिए, हमें यह तय करने के लिए अंततः खंड (1) पर वापस जाना होगा कि क्या प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं को की गई विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति को इसके तहत जारी अधिसूचित आदेश द्वारा विनियमित किया जा सकता है या नहीं, और उस प्रश्न का उत्तर, हमारे में होना चाहिए राय, सकारात्मक रहें।

19. इस संबंध में, एस का उल्लेख करना उचित हो सकता है। 3(2)(बी) जो उन कीमतों को नियंत्रित करने का प्रावधान करता है जिन पर कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सकती है। यह समझना आसान नहीं है कि यह खंड उन वस्तुओं को क्यों नहीं ले सकता है जिन्हें राज्य द्वारा खरीदा या बेचा जा सकता है। यह खंड इस प्रकार लिखा गया है कि सभी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लेनदेन इसमें शामिल होंगे। यह सच है कि जहां राज्य अपनी आवश्यक वस्तुएं बेचना चाहता है, वह कार्यकारी आदेश के माध्यम से कीमतों को विनियमित करने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है; लेकिन यह शब्दों के प्रभाव को समझने में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण नहीं है; यदि ये शब्द राज्य द्वारा बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को अपने दायरे में लेते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि राज्य को इस संबंध में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक अधिसूचित आदेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए।

20. राज्य द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद के संबंध में स्थिति अभी भी स्पष्ट है। यदि राज्य आवश्यक वस्तुएं खरीदना चाहता है, तो ऐसी वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से एस में शामिल होगी। 3(2)(बी). दरअसल, अपने तर्कों के दौरान, श्री सीतलवाड ने इस स्थिति पर गंभीरता से विवाद नहीं किया। इसलिए, जब राज्य आवश्यक वस्तुएं खरीदना चाहता है, तो वह एस के तहत जारी एक अधिसूचित आदेश के माध्यम से उस संबंध में कीमत को नियंत्रित कर सकता है। 3(1) और इससे पता चलता है कि राज्य द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और खरीद दोनों के मामलों में, एस। 3(2)(बी) एस के साथ पढ़ें। 3(1) राज्य को प्रासंगिक अधिसूचित आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करेगा।

21. फिर, श्री सीतलवाड द्वारा यह तर्क दिया गया कि विनियमित करने की शक्ति प्रतिवादी को एस द्वारा प्रदत्त है। 3(1) में टैरिफ दर बढ़ाने की शक्ति शामिल नहीं हो सकती; इसमें दरों को कम करने की शक्ति शामिल होगी। यह तर्क पूरी तरह से ग़लत है। "विनियमित करें" शब्द इतना व्यापक है कि यह प्रतिवादी को या तो दर बढ़ाकर, या दर घटाकर विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, परीक्षण यह है कि आपूर्ति को बनाए रखने, बढ़ाने या सुरक्षित करने के लिए क्या करना आवश्यक या समीचीन है। प्रश्न में आवश्यक वस्तुओं और उनके समान वितरण और उचित कीमतों पर उनकी उपलब्धता की व्यवस्था करना। उचित मूल्य की

अवधारणा जिससे एस. 3(1) स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक बार तय की गई कीमत या तो स्थिर रहनी चाहिए, या विनियमित करने की शक्ति को आकर्षित करने के लिए कम की जानी चाहिए। विनियमित करने की शक्ति का प्रयोग उचित मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, और उचित मूल्य का निर्धारण अनिवार्य रूप से उन सभी प्रासंगिक और आर्थिक कारकों पर विचार करने पर निर्भर करेगा जो इस तरह के उचित मूल्य के निर्धारण में योगदान करते हैं। यदि सभी प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष विचार करने पर बताई गई उचित कीमत निर्धारित और प्रचलित कीमत से अधिक हो जाती है, तो कीमत को विनियमित करने की शक्ति में कीमत को बढ़ाने की शक्ति आवश्यक रूप से शामिल होनी चाहिए ताकि इसे उचित बनाया जा सके। इसीलिए हमें नहीं लगता कि श्री सीतलवाड यह तर्क देने में सही हैं कि भले ही प्रतिवादी के पास उन कीमतों को विनियमित करने की शक्ति हो सकती है जिस पर अपीलकर्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जानी चाहिए, लेकिन उसे उक्त कीमत को बढ़ाने की शक्ति थी। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि विवादित अधिसूचित आदेशों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे एस के दायरे से बाहर हैं। 3(1) कायम नहीं रखा जा सकता.

22. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या विवादित अधिसूचित आदेश अमान्य हैं, क्योंकि वे कला के प्रावधानों का उल्लंघन

करते हैं। संविधान के 19(1)(एफ) और (जी)। आक्षेपित आदेशों को प्रतिवादी को प्रदत्त शक्ति के आधार पर अधिसूचित किया गया है। 3(1) और, इसलिए, कला के प्रयोजन के लिए कानून के रूप में माना जा सकता है।

19. हम अपीलकर्ताओं के पक्ष में यह भी मान सकते हैं कि समझौतों में निर्दिष्ट दरों पर बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार एक अधिकार है जो कला के अंतर्गत आता है। 19(1)(एफ) या (जी)। फिर भी, क्या यह कहा जा सकता है कि आक्षेपित अधिसूचित आदेश उचित नहीं हैं और आम जनता के हित में हैं? यही वह प्रश्न है जो वर्तमान विवाद से निपटने के लिए उत्तर की मांग करता है। यह सच है कि विवादित अधिसूचित आदेश जारी करके, प्रतिवादी ने अपने संबंधित अनुबंधों के लिए पार्टियों के बीच सहमत दरों को सफलतापूर्वक बदल दिया है और यह, प्रथम दृष्टया, अनुचित प्रतीत होता है। लेकिन, दूसरी ओर, साक्ष्य से पता चलता है कि जो टैरिफ कई साल पहले तय किया गया था वह पूरी तरह से पुराना हो गया था और समय-समय पर महालेखाकार द्वारा की गई रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहा था। सहमत दरें भले ही साल-दर-साल घाटा उठा रही थीं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित अधिसूचित आदेश गुण-दोष के आधार पर उचित नहीं था। इस बीच सभी वस्तुओं की कीमतें और श्रम शुल्क बहुत अधिक बढ़ गए हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा की

आपूर्ति के लिए टैरिफ बढ़ाने का मामला निश्चित रूप से तैयार हो गया है। लेकिन यह मानना संभव नहीं हो सका कि दरों में की गई वृद्धि से अपीलकर्ताओं के अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध उचित है और आम जनता के हित में है क्योंकि आक्षेपित आदेश ने प्रतिवादी को इसके तहत होने वाली आवर्ती हानि से बचा लिया है। ठेके। यदि इस तरह के व्यापक और सामान्य तर्क को स्वीकार कर लिया गया, तो कुछ मामलों में इसके अनुचित और यहां तक कि असंगत परिणाम भी हो सकते हैं। हालाँकि, इस प्रश्न पर व्यापक समुदाय के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए; और इस प्रकार विचार करने पर, जो बिंदु विवादित आदेशों की वैधता का समर्थन करता प्रतीत होता है वह यह है कि ये आदेश केवल विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किए गए थे और यह स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय की भलाई के लिए होगा। जब तक कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, यह जोखिम था कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति स्वयं ही समाप्त हो सकती थी। यदि प्रतिवादी ने सोचा कि अपीलकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के परिणामस्वरूप साल-दर-साल सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान हो रहा है, तो उसे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या आपूर्ति में कटौती नहीं की जानी चाहिए या पूरी तरह से बंद नहीं की जानी चाहिए। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि प्रतिवादी ने बड़े पैमाने पर जनता के प्रति अपने दायित्व को पहचाना और सोचा कि उन उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करना जो इसे लाभ कमाने के उद्देश्यों के लिए

उपयोग कर रहे थे, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर उचित और वैध नहीं होगा, और यह आशंका थी कि विधायिका इस तरह के पाठ्यक्रम के औचित्य या बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा सकती है; और इसलिए, अनुबंधों को समाप्त करने के बजाय, उचित मूल्य पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया और इसीलिए विवादित अधिसूचित आदेश जारी किए गए। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे सामने ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है कि विवादित अधिसूचित आदेशों द्वारा तय की गई कीमतें, किसी भी मायने में, अनुचित या अत्यधिक हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि संशोधित टैरिफ भी संभावित रूप से लागू होना चाहिए, न कि पूर्वव्यापी रूप से। इसलिए, इस मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हैं कि अधिसूचित आदेशों द्वारा टैरिफ में किए गए बदलाव को उचित और आम जनता के हित में माना जाना चाहिए।

23. श्री सीतलवाड ने विवादित आदेशों की वैधता को इस आधार पर चुनौती देने का भी प्रयास किया कि वे कला का उल्लंघन करते हैं। संविधान के 14. इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने हमारा ध्यान 1956 की रिट याचिका संख्या 923 में लगाए गए आरोप की ओर आकर्षित किया। उस रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि समझौतों के तहत निर्धारित दर नहीं बदली है और अब तक स्थिर बनी हुई है। राज्य सरकार के लाइसेंसधारकों के अधीन उपभोक्ता चिंतित थे। हलफनामे में यह माना गया है कि कुछ अन्य लाइसेंसधारियों ने अपनी दरों में वृद्धि की है,

लेकिन यह दावा किया गया है कि यह वृद्धि नगण्य या नाममात्र थी; और इसलिए, तर्क यह था कि जो दरें उपभोक्ता और उपभोक्ता के बीच व्यापक रूप से भिन्न हैं, वे कला का उल्लंघन हैं।

14. श्री सीतलवाड ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ये आरोप अस्पष्ट और अनिश्चित हैं और न तो याचिकाकर्ता द्वारा, जिसने यह हलफनामा दिया है, या किसी अन्य याचिकाकर्ता द्वारा, जो इस मामले की वैधता को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय चले गए, कोई अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। आदेश. वास्तव में, हम नहीं जानते कि अन्य लाइसेंसधारियों द्वारा ली जाने वाली दरें क्या हैं और हैं, और उनकी तुलना मूल अनुबंधों द्वारा निर्धारित दरों के साथ-साथ विवादित अधिसूचित आदेशों द्वारा बढ़ाई गई दरों से कैसे की जाती है। हमें यह जोड़ना चाहिए कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने गलती की है जब उसने यह मान लिया कि प्रतिवादी आंध्र राज्य में विद्युत ऊर्जा का एकमात्र आपूर्तिकर्ता था। यह सच है कि अधिकांश ऊर्जा की आपूर्ति प्रतिवादी द्वारा की जाती है; लेकिन कुछ अन्य निजी लाइसेंसधारी भी हैं जिनके पास उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने का लाइसेंस है और इस अर्थ में, प्रासंगिक समय में प्रतिवादी बिजली की आपूर्ति के मामले में एकाधिकारवादी नहीं था। इस न्यायालय ने बार-बार बताया है कि जब कोई नागरिक किसी क़ानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती देना चाहता है कि यह कला का उल्लंघन है। 14, उस संबंध में विशिष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट आरोप लगाए

जाने चाहिए और यह दिखाया जाना चाहिए कि विवादित क़ानून भेदभाव पर आधारित है और ऐसा भेदभाव किसी भी वर्गीकरण के लिए संदर्भित नहीं है जो तर्कसंगत है और जिसका उद्देश्य के साथ संबंध है उक्त क़ानून द्वारा प्राप्त किया गया। उस दृष्टिकोण से निर्णय लेने पर, वर्तमान समूह को बनाने वाली किसी भी अपील के रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिस पर कला के तहत कोई दलील दी गई हो। 14 को बढ़ाया भी जा सकता है. इसलिए, हमें नहीं लगता कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाना जरूरी है।

24. परिणामत: अपीलें विफल हो जाती हैं और सव्यय खारिज की जाती हैं। सुनवाई शुल्क का एक सेट.

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अविनाश चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।